

सार-समाचार

चीफ शहर काजी बने ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के चूरू जिलाध्यक्ष

रतनगढ़ (निसं)। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान प्रदेश के तत्वावधान में जोधपुर में आयोजित अखिल भारतीय हज खिदमतगार सम्मेलन–2026 में रतनगढ़ के चीफ शहर काजी रजामुराद अलवी एडवोकेट को ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी का चूरू जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मनोयन पर सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं गणमान्यजनों ने खुशी जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि रजा मुराद अलवी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से समाज सेवा और हज यात्रियों की खिदमत के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकीत खान, राष्ट्रीय महासचिव सैयद रियाज, प्रदेश अध्यक्ष ईतखाब आलम सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहे।

सीकर जिले में 29.8 लाख लोगों की आभा आईडी बन चुकी है

सीकर (निसं)। जिलेवासियों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में डिजिटल अखिल भारतीय सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जिले में गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएमएचओ डॉ. अशोक महरिया ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) बनाया जाता है। यह 14 अंकों की विशिष्ट हेल्थ आईडी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से संबंधित रिकार्ड को डिजिटल रूप में अपने फोन में रख सकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी नागरिकों की आभा आईडी बनाने तथा स्वास्थ्य रिकार्ड को आभा से लिंक करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एबीडीएम के तहत स्कैन एंड शेयर सुविधा के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन कर ओपीडी पंजीयन की प्रक्रियान को आसान बनाया गया है। इससे मरीजों को पंजीयन काउंटर पर लगने वाली कतार से राहत मिलती है और डिजिटल माध्यम से ओपीडी पंजीयन किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए चिकित्सा संस्थानों में फास्ट ट्रेक काउंटर विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। जिले के अधिकार क्षेत्रों पर इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से रोगियों को स्वास्थ्य रिकार्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी।

मीटर कंट्रोल लाइन को लेकर चूरू सांसद राहुल कस्वां ने मुख्यमंत्री से मांगा स्पष्टीकरण

सादुलपुर (निसं)। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे प्रस्तावित 4०/75 मीटर कंट्रोल लाइन के क्रियान्वयन से उत्पन्न हो रही जन-चिंताओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। सांसद ने कहा कि इस विषय को लेकर प्रदेश के हजारों निवासी, व्यापारी, किसान एवं संपत्ति स्वामी अपने मकानों, प्रतिष्ठानों तथा आजीविका के भविष्य को लेकर असमंजस एवं चिंता की स्थिति में हैं। सांसद कस्वां ने पत्र में लोकसभा में उनके द्वारा पूछे गए अतारंकित प्रश्न के उत्तर का उल्लेख करते हुए बताया कि सड़क पर परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 4०/75 मीटर कंट्रोल लाइन के संबंध में मंत्रालय द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फोरेलन ड्रेटिना प्रकरण में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में बिल्डिंग लाइन एवं कंट्रोल लाइन का विनियमन, अधिसूचना जारी करना तथा उनका क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार एवं दायित्व के अंतर्गत आता है। सांसद ने कहा कि बिल्डिंग लाइन एवं कंट्रोल लाइन का निर्धारण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है तथा विभिन्न राज्यों में इस संबंध में अलग-अलग नियम एवं प्रावधान लागू हैं। ऐसे में राजस्थान की जनता को राज्य सरकार की नीति, लागू नियमों एवं इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट एवं अधिकृत जानकारी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

पंचायत समिति में विधिक सेवा केंद्र पर ग्रामीणों को दी कानूनी जानकारी

रतनगढ़ (निसं)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू एवं तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ के निर्देशानुसार पंचायत समिति रतनगढ़ परिसर स्थित विधिक सेवा केंद्र में बुधवार को ग्रामीणों को विधिक सेवाएं व कानूनी जानकारी प्रदान की गई। निर्धारित कार्य दिवस के अवसर पर पीपलवी अधिकार मित्र जितेंद्र कुमार नाथोलिया ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं तथा उन्हें विभिन्न कानूनी प्रावधानों, निःशुल्क विधिक सहायता, उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान पंचायत समिति से देवकीनंदन जोशी सहित ग्रामीणजन मौजूद रहे। अधिकार मित्र नाथोलिया ने बताया कि जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति विधिक सेवा केंद्र के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने व किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में विधिक सेवा केंद्र से संपर्क करने का आह्वान किया।

पूर्व प्रधानाध्यापक ने विद्यालय में स्कूल बैग बांटे

पाटन (निसं)। राजकीय उत्कृष्ट बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मावंडा आरएस में बुधवार को विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक रामप्रसाद निवासी नयाबास की ओर से विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए गए। बैग पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। विद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका श्रीमती बनीता सैनी ने पूर्व प्रधानाध्यापक रामप्रसाद की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के सामाजिक सहयोग से विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ता है और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरणा मिलती है।

नोहर में विधायक ने 1.2० करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया

- विकास कार्य केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका लाभ आमजन को धरातल पर मिलना चाहिए : विधायक अमित चाचाण**

ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

विधायक ने कहा कि रतनपुरा में लगभग 1.2० करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए विकास कार्य ग्रामीणों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका लाभ आमजन को धरातल पर मिलना चाहिए। क्षेत्र की जनता द्वारा बताई जाने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है।

गांव के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए भविष्य में भी आवश्यकता के अनुसार नए विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने ग्रामीणों से विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने में सहयोग करने तथा गांव के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

इस मौके पर विधायक ने कार्यकर्ताओं से निकले हुए पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने गांव कि प्रत्येक समस्या का समाधान करवाया है वहाँ से जो समस्याएं चली आ रही थी उनका स्थाई समाधान करवाया गया समारोह में मंच संचालन दयाराम देवड़ा ने किया। कार्यक्रम में पौसीसी सदस्य

आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन सीटू की नई कार्यकारिणी गठित

रतनगढ़ (निसं)। आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन सीटू रतनगढ़ की बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। ममता पारीक को अध्यक्ष, मुन्नी शर्मा को सचिव, रंजना चौमाल को कोषाध्यक्ष, शिवानी भाटी व प्रेमलता को उपाध्यक्ष चुना गया। संगठन सलाहकार सुमन दाधीच व रामप्यारी जाट, संगठनमंत्री मुक्ता सोनी व पूजा प्रजापत तथा पंचार मंत्री मनभरी जाट व छोटू मेघवाल बनाए गए।बैठक में बकाया मागदेय, भवन व बिजली क्रियाया, प्रोत्साहन राशि, पोषाहार राशि एवं पीएमएनबीवाई के लंबित भुगतानों सहित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। शुभकरण नैन, रामकृष्ण छीपा व रमेश चौधरी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष का आह्वान किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ममता पारीक ने कार्यकर्ताओं के हित में मजबूती से संघर्ष करने की बात कही।

संस्थान सचिव कमल शर्मा ने बताया कि युवा कवि चारण को चूरू

नागौर के सत्येन्द्र चारण को पुरस्कार मिलेगा

जयपुर/चूरू (कासं)। प्रयास संस्थान चूरू द्वारा राजस्थानी भाषा के पैंतीस वर्ष से कम के युवाओं को दिया जाने वाला वार्षिक दुर्गाेश युवा पुरस्कार वर्ष 2०26 के लिए गांव झोरड़ा, नागौर के युवा कवि सत्येन्द्र चारण को दिया जाएगा। प्रयास संस्थान के संस्थापक डॉ. दुलाराम सहारण ने बताया कि 1० अगस्त 1998 को नागौर के गांव झोरड़ा निवासी सत्येन्द्र चारण को उनकी काव्यकृति ‘भीत भरोसे री’ के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा।

संस्थान सचिव कमल शर्मा ने बताया कि युवा कवि चारण को चूरू

खेती-किसानी से जुड़े विभिन्न मुद्हों पर सांसद कस्वां की केन्द्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात

चूरू (कासं)। सांसद राहुल कस्वां ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखा। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का मुद्दा उठाते हुए सांसद कस्वां ने कहा कि राजस्थान और खासकर शेखावाटी क्षेत्र व बीकानेर संभाग देश में मुख्य मूंग उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 5.23 लाख टन मूंग खरीद का लक्ष्य रखा गया है, और इस खरीद में से अधिकतर हिस्सा केवल एक ही राज्य से किया जा रहा है। पिछले दिनों मध्यप्रदेश के किसानों व किसान संगठनों के द्वारा मूंग की 1०० फसल उत्पाद को समर्थन मूल्य पर खरीद किये जाने हेतु आंदोलन किया गया, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा कुल उत्पादन की 25 की खरीद सीमा को बढ़ाकर 6० कर दिया गया है।

राजस्थान वैसे ही असिंचित क्षेत्र है व अधिकतर वर्षा आधारित खेती होती है, विपरीत परिस्थितियों के चलते यहां का किसान लगातार काफी आर्थिक नुकसान में रहता है। इसके बावजूद भी खरीद किये जाते समय अनेक प्रकार की शर्तें किसानों पर थोपी जा रही हैं, जिसके कारण किसानों की तय सीमा में की जा रही खरीद भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। अतः केंद्र सरकार इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर राजस्थान के किसानों से भी 1०० मूंग की खरीद समर्थन मूल्य पर करने की व्यवस्था करवाया, जिससे किसानों को संबल मिल सके।

सांसद कस्वां ने पीएम धन्य धान्य योजना से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजस्थान के 8 जिलों का चयन इस योजना के तहत किया गया है, जहां दलहन की 1०० प्रतिशत खरीद किये जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन

में प्रस्तावित समारोह में पुरस्कार स्वरूप इक्कावन सौ रुपये नगद, शॉल, श्रीफल और मानपत्र प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चूरू के दिवंगत साहित्यकार दुर्गाेश स्मृति में संस्थान द्वारा वर्ष 2०16 से प्रारंभ इस पुरस्कार से अवतक कालू-बीकानेर के कमलकिशोर पीपलवा, उदयपुर की रीना मेनारिया, सूरतगढ़ के सतीश छीपा, राजपुरा-तारानगर के उम्मेद धानिया, जैसलमेर के महेंद्रसिंह छावण, गुसाईंसर बड़ा-बीकानेर के पूनमचंद गोदारा, झाक-बाड़मेर के जेठानंद पंवार आदि युवा साहित्यकार समादृत हो चुके हैं।

- खरीद करते समय अनेक प्रकार की शर्तें किसानों पर थोपी जाती हैं, जिस कारण उनकी तय सीमा में की जा रही खरीद भी पूर्ण नहीं हो पाती : राहुल कस्वां**

भारत सरकार ने योजना में तुअर, उड़द व मसूर दाल को ही इसमें शामिल किया है। राजस्थान के चर्यानित 8 जिलों में इन दालों का उत्पादन नगण्य है, जबकि मूंग और चना जैसी बहुतायत में उत्पादित होनी वाली दलहनी फसलों को योजना से बाहर रखा गया है। चना व मूंग दाल को शामिल नहीं किए जाने के कारण उक्त योजना किसानों के लिये कतई लाभकारी साबित नहीं हो पा रही है। अतः किसान हित को देखते हुए पीएम धन-धान्य योजना में मूंग व चना फसलों को शामिल किया जाए।

साथ ही इस योजना के दिशा-निर्देशों में भारत सरकार ने शत्येक जिला स्तर व राज्य स्तर पर समिति के गठन का प्रावधान किया है, लेकिन इस समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किसान संगठनों को शामिल नहीं किया गया है। किसानों से जुड़ी मुख्य समस्याओं और सुझावों को रखने वाला कोई किसान प्रतिनिधि इन समितियों में नहीं होने से योजना के उचित क्रियान्वयन और लाभ की सुनिश्चिता प्रभावित होनी तय है। अतः इस अति महत्वपूर्ण विषय पर अवलंब विचार कर जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय समिति में जनप्रतिनिधि व किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव

फिनटेक के साथ युवा कौशल विकास और वित्तीय स्वायत्तता कार्यक्रम एवं युवा स्टार्ट-अप एवं युवा उद्यमियों के साथ संवाद

गरिमामयी उपस्थिति

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्रीमती निर्मला सीतारामन
माननीया वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, भारत सरकार

लोकार्पण

• सब-रीजनल साइंस सेंटर, उदयपुर • न्यूक्लियर पावर गैलरी, रीजनल साइंस सेंटर, जयपुर • 7डी थिएटर, रीजनल साइंस सेंटर, जयपुर

शिलान्यास

• डिजिटल प्लेनेटेरियम, उदयपुर • डिजिटल प्लेनेटेरियम, जोधपुर

शुभारंभ

• राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट 2026
• स्टेट होलिस्टिक प्रोक्वोरमेंट पोर्टल (SHPP)
• राजस्थान फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के लिए MoU के माध्यम से फिनटेक कोर्सेज

MoU/ DBT / अन्य

• भारत के चार शहरों में आईस्टार्ट सुविधा डेस्क स्थापित करने के लिए एसटीपीआई (STPI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर
• पीएमएवाई-ग्रामीण (PMAY-G) और पीएमएवाई-शहरी (PMAY-U) के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
• राजस्थान के चयनित स्टार्टअपस को फंडिंग







दिनांक : 13 अगस्त, 2026 | समय : दोपहर 12:30 | स्थान : राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIAC), झालाना, जयपुर

वित्त विभाग, राजस्थान